Sir, I urge the Government, through you, to establish a nodal agency to control cancer in our country. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Shri Sandosh Kumar P: Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).

Concern over rising cases of Cyber Crimes in the country

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस सदन का ध्यान बढ़ते हुए साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। इसमें 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रेंड नेम के दुरुपयोग से होंगे। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 8,200 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनकी मेहनत की कमाई कुछ सेकेंड्स में लुट जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए वर्षों से पैसे जोड़ रहा था और शादी के ठीक पहले एक साइबर अपराधी ने उसके सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। उसकी हालात यह हुई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। इस तरीके के बहुत सारे मामले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कई बुजुर्गों की पेंशन भी उनके अकाउंट से गायब हो जाती है। छोटे-छोटे व्यापारियों की पूंजी खत्म हो जाती है। जहां हम लोग देश के अंदर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी की प्राथमिकता भी उतनी ही होनी चाहिए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनिवार्य तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाए। छोटे और ग्रामीण बैंकों को भी अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए। साइबर अपराध की जांच के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले। साइबर क्राइम पीड़ितों के लिए एक compensation fund भी बनाया जाए, जिससे निर्दोष लोगों की खोई हुई राशि वापस मिल सके।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि साइबर बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि हर नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Shri Sanjay Seth: Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Dr. Fauzia Khan; not present. Shri Dhairyashil Mohan Patil – Demand for establishment of Multifunctional Development Centres in Raigad districts of Maharashtra for its comprehensive development.

Demand for establishment of Multi-Functional Development Centres in Raigad district of Maharashtra for its comprehensive development

श्री धैर्यशील मोहन पाटिल (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभापति महोदय, रायगढ़ जिले में औद्योगिक विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के मुद्दे पर मैं अपनी अपेक्षा यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ ही यहाँ एक अच्छा तटीय क्षेत्र भी है। इसके साथ ही, यहाँ एक ओर जेएनपीटी, धरमतार, दिघी जैसे बंदरगाह हैं, तो दूसरी ओर तलोजा, महाड, रसायनी जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। इस जिले में कृषि उद्योग, मत्स्यपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा potential माना जाता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय युवकों को रोजगार मिलने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए उनको कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करना भी बहुत जरूरी है। मौजूदा प्रशिक्षण सुविधा इस आवश्यकता का पूरे तरीके से समाधान करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हो जाते हैं। उपसभापति महोदय, जिला कार्य योजना के अनुसार जितने कुशल कार्यबल प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, इस जिला को उससे कई गुना ज्यादा कुशल कार्यबल की आवश्यकता है।

उपसभापति महोदय, मेरी अपेक्षा है कि सरकार को जेएनपीटी, दिघी जैसे क्षेत्रों में जो औद्योगिक कंपनियाँ हैं, औद्योगिक संगठन हैं, उनके साथ मिल कर बहुक्षेत्रीय कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे स्थानीय युवक-युवतियाँ कुशल कार्यबल में प्रशिक्षित हो सकें, जिससे स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार मिल सके और इस जिले का समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। उपसभापति महोदय, मेरी अपेक्षा है कि यह जिला जिस आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति का हकदार है, वह हक इस जिला को मिले, यहाँ के युवक-युवतियों को मिले। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde – Demand for conferring the Bharat Ratna Award posthumously on the late Dr. Panjabrao Shamrao Deshmukh.

Demand for conferring the Bharat Ratna Award posthumously on the late Dr.Panjabrao Shamrao Deshmukh

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के लिए विशेष रूप से शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र में महान योगदान देने वाले स्वर्गीय डा. पंजाबराव